



DAY 32°
NIGHT 28°
Hi Low

संक्षेप

गणेशोत्सव पर कोंकण जाने वाले भक्तों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, 11 से 27 सितंबर तक टोलमाफी मुंबई। गणेशोत्सव के अवसर पर कोंकण स्थित अपने गांव जाने वाले गणेश भक्तों को महाराष्ट्र सरकार ने राहत दी है। राज्य सरकार ने 11 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक कोंकण की ओर जाने वाले गणेश भक्तों के वाहनों को टोलमाफी देने का फैसला किया है। लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। सरकार ने टोलमाफी के लिए अलग पास और स्टिकर की भी व्यवस्था की है, जो वापसी की यात्रा में भी मान्य होंगे। सरकार के अनुसार, यह छूट मुंबई-बेलातुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग-66 और लोक निर्माण विभाग तथा महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के अंतर्गत आने वाले कोंकण मार्गों पर स्थित टोल नाकों पर लागू होगी। इसके अलावा, नगर विकास विभाग के अधीन अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी-हावावा अटल सेतु से कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों के वाहनों की भी टोलमाफी का लाभ मिलेगा। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई, ठाणे, पुणे समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग कोंकण स्थित अपने मूल गांव जाते हैं। इस कारण मुंबई-गोवा राजमार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या काफी बढ़ जाती है। सरकार का कहना है कि टोलमाफी से श्रद्धालुओं पर यात्रा का अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा और उनका सफर अधिक सुगम बनाया जा सकेगा। टोलमाफी का लाभ लेने के लिए 'गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन' लिखे स्वतंत्र स्टिकर या पास उपलब्ध कराए जाएंगे। पास पर वाहन का नंबर और चालक का नाम दर्ज होगा। पुलिस स्टेशन, यातायात पुलिस चौकियों और आरटीओ कार्यालयों सहित आवश्यक स्थानों पर पास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। यह पास वापसी के दौरान भी मान्य रहेगा।

मनोज जरांगे बोले- 'सरकार को घुटनों पर लाएंगे', मराठा समाज के लोगों से की आत्महत्या न करने की अपील मुंबई। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि मराठा समाज मुंबई आने के लिए तैयार है। हम सरकार को घुटनों पर लाएंगे। मराठा समाज पीछे नहीं हटेंगा। इसके साथ ही, मनोज जरांगे ने मराठा समाज से अपील करते हुए कहा कि हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन कोई भी आत्महत्या न करे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत मनोज जरांगे ने कहा कि अगर मराठा समाज के लोग आत्महत्या करते हैं, तो सरकार को उसका कोई दुख नहीं है। सरकार ने मराठों की जान ली है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं आरक्षण लिए बिना चुप नहीं बैठूंगा। बार दिन दर होगी, लेकिन आरक्षण निश्चित रूप से मिलेगा। आपमें से कोई भी आत्महत्या मत करो, यह हाथ जोड़कर विनती है। सरकार की मराठों के प्रति भूमिका यह है कि सरकार ने मराठों का विनाश करने का तय किया है। ऐसे समय में हम सभी को एकजुट होकर संकट का सामना करना होता है। हाताश होकर आत्महत्या नहीं करनी होती। हमें सरकार का सामना करना होता है।

आर्यावर्त क्रांति

हिंदी दैनिक

पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन बोले- भाजपा चलाएगी संकल्प सेवा अभियान

'प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा की यात्रा जारी'

नई दिल्ली, एंजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने और उनके जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी महीने भर का 'सेवा संकल्प' अभियान शुरू करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान देशभर में सेवा और जनकल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। अभियान के पहले दिन यानी 17 सितंबर को देशभर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। इसी दिन शाम 7 बजे



'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम भी आयोजित होगा। नवीन ने कहा, 'प्रथम दिन यानी 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।

उसी दिन शाम को सात बजे 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम होगा। इस पूरे कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य यह दर्शाना है कि पिछले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री जी

पट्टे पर दिया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार, शुभम त्यागी और सुधांशु किराए पर ली गई संपत्ति को 'हॉस्टल डेज' नाम से पीजी (पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन) के रूप में चला रहे थे। वहीं, दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने के मामले में गिरफ्तार मकान मालिक के बेटे महेश को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। महेश की पुलिस कस्टडी बुधवार को खत्म हो रही है। कोर्ट ने सोमवार को महेश को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। वहीं, उर्मिला और हरिराम को मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, पूछताछ में महेश ने बताया कि वह अपने माता-पिता (उर्मिला और हरिराम) की ओर से इमारत के रखरखाव का काम देखा था।



पेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि वहीं महिलाएं जमीन पर सो रही हैं और जानवर बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी भी घाट पर चले जाएं, आपको महिलाएँ जमीन पर सोती हुई मिलेंगी, जानवर पानी में हैं और चारा भी गीला हो गया है। उन्होंने बेघर हुए लोगों और बाढ़ वाले इलाकों में फैसे लोगों की मुश्किलों पर जोर दिया। यादव ने प्रभावित लोगों को सन्तुष्ट किए जा रहे पीने के पानी की

क्वालिटी पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि टैंकों से जो पानी भेजा जा रहा है, वह इतना खराब है कि नेता खुद उसे नहीं पिएँगे। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी चीजों की सप्लाई भी खराब हो रही है; बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है और दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हैं, जबकि कुछ जगहों पर बिजली पूरी तरह से गुल है। उन्होंने कहा कि टैंकर का पानी इतना खराब है कि कोई भी नेता इसे नहीं पिएगा।

साफ कर दिया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी मजिस्ट्रेट उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार, 9 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के एजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने CJP प्रोसेस्ट में शामिल होने के लिए प्रचार करने वाले एक छात्र के खिलाफ 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 130 के तहत जारी नोटिस पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि एजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने यह नोटिस कैसे जारी किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी FIR को रद्द कर दिया था और CJP विरोध प्रदर्शनों को लेकर किसी भी छात्र के खिलाफ भविष्य में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। यह मामला सीनियर एडवोकेट

'PM के प्रति आभार जताने के लिए जलाएंगे दीप' नितिन नवीन ने बताया कि लाभार्थी परिवार प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताने के लिए दीप जलाएंगे। इसे 'जन आशीर्वाद' के सामूहिक प्रदर्शन के तौर पर आयोजित किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, 'हम जन आशीर्वाद सामूहिक प्रदर्शन के रूप में प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। प्रत्येक लाभार्थी परिवारों द्वारा प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के रूप में ये दीप जलाए जाएंगे।' बीजेपी के मुताबिक, पूरे अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों में हुए बदलावों और उनकी जनसेवा को लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

ने निष्ठा के साथ जनसेवा की है।' **केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे सामने**

पार्टी का कहना है कि अभियान के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके लाभार्थियों की उपलब्धियों को भी सामने रखा जाएगा। नितिन नवीन

ने कहा कि बीजेपी मोदी की जनसेवा का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाएगी। उन्होंने महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व संबंधी विकास की बात की, और उनके नेतृत्व में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ से जिस सफर की शुरुआत हुई, वह आज



पहुंच गई है। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के दो सी-2 पजिवहन विमान जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर उतरे थे। इनके पहुंचने के साथ ही जापानी दल ने अभ्यास में अपनी भागीदारी शुरू कर दी है। वायुसेना के मुताबिक, 'वीर गार्जियन 2026 के दौरान दोनों देशों की वायु सेनाएं और ऑपरेशनल गतिविधियों में हिस्सा लेंगी। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं के

बीच ऑपरेशनल तालमेल, युद्धक क्षमताओं और आपसी समझ को बेहतर बनाना है। जोधपुर का आसमान आने वाले दिनों में भारत और जापान के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की गतिविधियों का गवाह बनेगा। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के एफ-2 लड़ाकू विमान भी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान इनके साथ संयुक्त हवाई अभियानों का अभ्यास करेंगे।

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

रायबरेली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के अंतिम दिन बुधवार को भुमरऊ गेस्ट हाउस में आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सुबह करीब नौ बजे शुरू हुए जनता दरबार में राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं एवं मांगें सुनीं। गेस्ट हाउस के बाहर लोगों की लंबी कतार नजर आई, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के तहत एक-एक व्यक्ति को अंदर प्रवेश दिया गया।

जनता दरबार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों और विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी से मुलाकात कर स्थानीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस

विश्वजीत भट्टाचार्य द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के ध्यान में मौखिक रूप से लाया गया। एडवोकेट विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा, 'नोएडा पुलिस की जानकारी पर ग्रेटर नोएडा के एजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दूसरे वर्ष के छात्र को नोटिस जारी किया था, इसे लागू किया जाने वाला था, बाद में प्रेस में खबर आई कि इसे वापस ले लिया गया है।' वकील ने आगे कहा, 'यह भारत के छात्रों के साथ एक प्रयोग है। यह प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना है। नोएडा और यूपी के अधिकारी छात्रों के मन में डर का माहौल नहीं बना सकते।' जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने पूछा कि अगर नोटिस वापस ले लिया गया है,

नई दिल्ली, एंजेंसी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारे सामने सब बराबर हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले के शिकायतकर्ता से कहा कि अगर वह मामले की जल्द सुनवाई चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए उचित आवेदन दायित्व करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उसके लिए सभी पक्ष समान हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत,

लखपति दीदी तक पहुंचा है। नारीशक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की महिलाओं को उनका अधिकार देने और नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास लगातार जारी है।'

युवाओं की उपलब्धियों का भी होगा जिक्र

बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक उपलब्धियों को भी अभियान का हिस्सा बताया। उन्होंने दावा किया कि 25 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। नवीन ने कहा, 'जब उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला, तो उस समय देश में निराशा और अंधकार का माहौल था। हमारी अर्थव्यवस्था को

ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले-अहीर और जहीर आपको निपटा देंगे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो **लखनऊ।** सुलेखदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा और तीखा सियासी हमला बोला है। राजभर ने प्रदेश में हालिया आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपने 'अहीर' और 'जहीर' को नियंत्रित करें, नहीं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 27 सीटें भी नहीं जीत पाएगी।

मंत्री राजभर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि अखिलेश भाई अपने 'अहीर' और 'जहीर' को कंट्रोल कॉलिए महाराज। ये बहुत अति मचाये हुए हैं। समाज का तो अहित कर ही रहे

हैं, आपको भी ये निपटा देंगे। उन्होंने कहा कि अभी कल की ही घटना देख लीजिए। झांसी में आपका 'अहीर', जो कि सरकारी मास्टर है, उसने एक व्यापारी, जो कि बनि्या समाज से आते हैं, उनका अपहरण कर लिया।

उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। जनता दरबार में महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। रायबरेली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लक्ष्मी सिन्हा ने राहुल गांधी को राखी बांधी और तिलक लगाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है।

उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि लक्ष्य के लिए अब थोड़ी और मेहनत की जरूरत है और कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटे हैं।

राहुल गांधी ने शहीद के सम्मान में स्मारक और चौराहा बनवाने का आग्रह किया, जिस पर राहुल गांधी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने

की गई है। **व्या है राहुल गांधी से जुड़ा यह मामला** राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला उनके उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं।' यह बयान राहुल गांधी की ओर से लाइन ऑफ एक्जुअल कंट्रोल (LAC) पर चीन की हथकौती को लेकर सरकार की आलोचना के तौर पर दिया गया था।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और रोजगार को मिलेगी नई गति, छह परियोजनाओं को मंजूरी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किसानों और उद्यमियों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत उद्यमियों को दी जा रही सुविधाओं, अनुदान और अन्य प्रावधानों की व्यापक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक उद्यम स्थापित हों और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिले।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों के कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाया जा सकता है। इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को

लंबित एफपीओ अनुमोदन और भुगतान को लेकर 600 प्रतिनिधियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

लखनऊ। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के करीब 500 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लंबित अनुमोदन तथा सामुदायिक व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) और एफपीओ के लंबित भुगतानों को लेकर प्रदेशभर के किसान उत्पादक संगठनों में अस्तोष बढ़ गया है। समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जाने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए बुधवार से लखनऊ में करीब 600 एफपीओ प्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।धरने पर बैठे एफपीओ प्रतिनिधियों का कहना है कि अनुमोदन और भुगतान में हो रही विभागीय एवं तकनीकी देरी का सीधा असर संस्थाओं की गतिविधियों पर पड़ रहा है। इससे एफपीओ के क्षमता

निर्माण, प्रशिक्षण और जमीनी स्तर पर संचालित होने वाले कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिनिधियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों के कारण संगठनों के सामने आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं।एफपीओ प्रतिनिधियों ने 30 सितंबर के बाद 200 रुपये प्रतिदिन संभावित दंड को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। उनका सवाल है कि यदि अनुमोदन और भुगतान में देरी विभागीय अथवा तकनीकी कारणों से हो रही है तो उसका आर्थिक दंड किसान उत्पादक संगठनों पर क्यों लगाया जाए। प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए विभागीय विलंब के लिए एफपीओ को जिम्मेदार न ठहराने की मांग की है।धरना दे रहे प्रतिनिधियों ने सभी लंबित एफपीओ के अनुमोदन की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने की मांग की है।

24 अक्टूबर से निकलेगी चाणक्य रथ यात्रा, पटना से दिल्ली तक गुंजेगा सामाजिक जागरण का संदेश

लखनऊ। अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की ओर से 24 अक्टूबर से चाणक्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का शुभारंभ आचार्य चाणक्य की जन्मभूमि पाटलिपुत्र, पटना से सुबह नौ बजे होगा। विभिन्न जिलों से होते हुए यात्रा 2 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगी, जहां संसद घेराव के कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा।

परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक पंडित कृष्णनिधान तिवारी ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य समाज में जन-जागरण, लोगों को अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक करना तथा वर्तमान व्यवस्था की विसंगतियों के प्रति सचेत करना है। यात्रा पटना, दानापुर, बिहटा, आरा, जगदीशपुर, दिनारा, कोचस, मोहनिया, सैफदराज, चंदौली, वागणसी, जौनपुर, शाहगंज, अकबरपुर, अयोध्याधाम, वारांबकी, लखनऊ, कानपुर, औरैया,



इटावा, आगरा, मथुरा, पलवल और फरीदाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा के प्रमुख मुद्दों में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, योग्यता आधारित पदों पर आरक्षण समाप्त करने, सर्वण आयोग का गठन, समान नागरिक संहिता लागू करने, भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने, अयोध्या में भगवान परशुराम मंदिर निर्माण तथा यूजीसी जैसे कानूनों को वापस लेने की मांग शामिल है। इसी क्रम में बुधवार को लखनऊ स्थित



भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रदेश सरकार इस क्षेत्र को निवेश, रोजगार और मूल्य संवर्धन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा

खाटू श्याम मंदिर परिसर में भव्य भजन संध्या आयोजित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय सनातन संघ द्वारा राजधानी लखनऊ के न्यू हैदराबाद, निशातगंज स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर परिसर में भव्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम 'एक शाम खाटू श्याम बाबा के नाम' का विशाल आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सनातन संघ के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र खरे के नेतृत्व में आयोजित इस भव्य भजन संध्या में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को शाम पांच बजे से खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर खाटू श्याम बाबा एवं भगवान श्रीकृष्ण की आराधना की और भक्तिमय वातावरण में आयोजित सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया।

इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायकों एवं कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक और भावपूर्ण

प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के माध्यम से उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार के साथ स्थानीय किसानों को बाजार उपलब्ध कराना और गांव-गांव तक औद्योगिक गतिविधियों का लाभ पहुंचाना है।खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण, तैयार खाद्य एवं तैयार पकाने योग्य खाद्य पदार्थ, नाश्ता अनाज, नमकीन, बेकरी उत्पाद, अनाज, दाल एवं तिलहन प्रसंस्करण सहित अनेक क्षेत्रों को नीति के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा मसाला, सोयाबीन, मशरूम, शहद, कोको उत्पाद, गुड़ आधारित मूल्य संबंधित उत्पाद, फलों के रस एवं गूदे, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ तथा मानव उपयोग के लिए उपयुक्त अन्य



भजनों की प्रस्तुतियों दी गईं। साथ ही मथुरा-वृंदावन के आकाशवाणी, दूरदर्शन , सूचना विभाग एवं संस्कृति विभाग से जुड़े ख्यातिप्राप्त कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कलाकारों की मधुर एवं मनोहारी प्रस्तुतियों से संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिरस में सराबोर हो उठा। भजन संध्या के दौरान श्याम बाबा के भजनों की मधुर स्वर लहरियों पर श्रद्धालु भावविभोर होकर झुमते और नृत्य करते नजर आए। पूरा मंदिर परिसर 'हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा' के जयकारों तथा भगवान श्रीकृष्ण एवं खाटू श्याम बाबा के उद्घोष से गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं

खाद्य उत्पादों के साथ मुर्गी और मछली चारा निर्माण इकाइयों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा निवेश प्रस्तावों के परीक्षण और स्वीकृति की प्रक्रिया को भी गति दी जा रही है। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 के अंतर्गत गठित अप्रेजल समिति की बैठक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में हुई। बैठक में कुल छह प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। समिति ने सभी प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के बाद आवश्यक शर्तों एवं निर्देशों के साथ स्वीकृति प्रदान की।स्वीकृत परियोजनाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र, चावल मिल, फल पूटा संयंत्र, तैयार

खाद्य एवं तैयार पकाने योग्य खाद्य पदार्थ निर्माण इकाइयां, बेकरी और आइसक्रीम उत्पादन इकाइयों सहित विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।समिति की बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं के सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। संबंधित उद्यमियों को परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। समिति ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में स्थानीय कृषि एवं दुग्ध उत्पादकों से कच्चे माल की खरीद को प्राथमिकता दी जाए।

परम्पराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्ज़ा, आध्यात्मिक चेतना और भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सनातन संस्कृति, भक्ति भावना, धार्मिक मूल्यों एवं जन-कल्याण के संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित करना है। राष्ट्रीय सनातन संघ के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र खरे ने इस अवसर पर कहा कि संस्था निरंतर सनातन संस्कृति, भारतीय परम्पराओं एवं सामाजिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित 'एक शाम खाटू श्याम बाबा के नाम' कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सनातन परम्पराओं एवं धार्मिक मूल्यों से जोड़ना तथा समाज में प्रेम, सद्भाव और समरसता का संदेश देना है।

अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, तभी आकाश की वापसी पर विचार हो सकता है : मायावती



लेकिन उन्होंने बहुजन मिशन से अधिक निजी और पारिवारिक स्वार्थ तथा महत्वाकांक्षा को महत्व दिया। पार्टी का कहना है कि इसका खामियाजा अशोक सिद्धार्थ के साथ उनके दामाद आकाश आनंद को भी भुगतना पड़ा है।

बयान में कहा गया कि अशोक सिद्धार्थ ने अपने निजी स्वार्थ में आकाश आनंद और बसपा मूवमेंट की भी पर्याप्त परवाह नहीं की। पार्टी

के मुताबिक, उनसे दूसरों की तुलना में अधिक त्याग, तपस्या और कुर्बानी की अपेक्षा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

चुनावी राज्यों पर बसपा का फोकस

मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं। पार्टी के अनुसार ये तीनों राज्य बहुजन

समाज और बहुजन मूवमेंट के लिए विशेष महत्व रखते हैं। पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक और शुभचिंतक इन राज्यों में सत्ता प्राप्त के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं।

मौजूदा समय में पार्टी और

बहुजन समाज को विरोधी दलों और जातिवादी तत्वों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वसमाज के लोगों से सहयोग की अपील करते

हमारे के सभी वर्गों से निजी या पारिवारिक स्वार्थ में ऐसा कोई कदम नहीं उठाने को कहा, जिससे आंदोलन के हित प्रभावित हों।

अनुशासन को लेकर सख्त रुख

मायावती ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व संगठन में भूले-भटके लोगों को उनके आचार-व्यवहार को ध्यान में रखते हुए शामिल कर रहा है। वहीं, पार्टी

की राह में बाधा बनने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। बयान में अशोक सिद्धार्थ को इसका चर्चित उदाहरण बताया गया है।

आकाश आनंद की जिम्मेदारियों पर भी संकेत
मायावती ने आकाश आनंद की भविष्य की भूमिका को भी अशोक सिद्धार्थ के फ़ैसले से जोड़ते हुए संकेत दिया है। यदि अशोक सिद्धार्थ राजनीति से संन्यास लेकर निजी स्वार्थ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर उठते हैं तो आकाश आनंद के लिए पार्टी में स्वतंत्र रूप से काम करना संभव होगा। ऐसी स्थिति में पार्टी आकाश आनंद को उनकी जिम्मेदारियां वापस देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है, ताकि वह संगठन में फिर सक्रिय भूमिका निभा सके।

एडेड स्कूलों के 811 तदर्थ शिक्षकों के लिए गुड न्युज, वर्षों से अटकी सैलरी मिलने का रास्ता साफ

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में वर्षों से पड़ा रहे वेतन न पाने वाले 811 तदर्थ शिक्षकों को भी जल्द वेतन दिया जाएगा। इसकी कानूनी अड़चनें दूर होंगी। सरकार इसके लिए नीति बनाएगी। कुल 1111 तदर्थ शिक्षकों में से अभी 300 शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। अब शेष शिक्षकों को भी मिलेगा। विधान परिषद में बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों को लेकर नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को समिति की बैठक हुई। इसमें विधान परिषद सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह व उमेश द्विवेदी ने यह मामला उठाया। शिक्षिका ईशा सिंह के प्रकरण पर कोर्ट के आदेश के बाद करीब 300 शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है।

एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडहॉक व्यवस्था खत्म करने को लेकर दिए गए आदेश के बाद इन तदर्थ शिक्षकों को बाहर किया गया। पूर्व में दिए गए आदेश में वर्ष 2021 तक नियमित शिक्षकों की व्यवस्था करनी थी। फिलहाल 300 शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है और बाकी 811 शिक्षकों से काम लिए जाने के बावजूद वेतन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में सरकार इन्हें लेकर नीति बनाए। बैठक में निर्देश दिए गए कि जल्द नीति बनाई जाए और बचे शिक्षकों को वेतन देने की तैयारी की जाए। वहीं साल 2024 में नियुक्त विधिज्ञ बीटीसी शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने, शिक्षाप्रप्त से शिक्षक बनने वालों की पुरानी सेवा जोड़कर उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ देने, 2000 के बाद नियमित शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने पर भी चर्चा की गई।



सत्य निकेतन हादसा: जिम्मेदार अधिकारियों पर हो ठोस कार्रवाई

दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को पांच मंजिला छात्र-पीजी भवन का भरभराकर गिर जाना केवल एक दर्दनाक हादसा नहीं है। यह उस व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जो भवन बनने देती है, उसमें अनधिकृत निर्माण होने देती है, उसमें विद्यार्थियों को रहने देती है, उसकी कमजोरियों को वर्षों तक नजरअंदाज करती है और फिर उसके ढह जाने के बाद जागती है।

इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की सूचना है और कई लोग घायल हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भवन में बेसमेंट और कई ऊपरी मंजिलों में मरम्मत या निर्माण संबंधी काम चल रहा था। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच और भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हादसे के बाद किसके खिलाफ एफआईआर होगी? असली सवाल यह है कि हादसे से पहले जिम्मेदार अधिकारी कहाँ थे? यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन था, यदि भवन का स्वीकृत नक्शा नहीं था, यदि अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं, यदि बेसमेंट में निर्माण चल रहा था, यदि भवन छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और यदि वह संरचनात्मक रूप से जोखिमपूर्ण था, तो इन सबका पता प्रशासन को तब क्यों नहीं चला जब वहां निर्माण हो रहा था? नएस्थान तलाशें

सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के आसपास विद्यार्थियों का प्रमुख इलाका है। देश के विभिन्न राज्यों से हजारों युवा यहां अपने भविष्य के सपने लेकर आते हैं। वे छोटे-छोटे कमरों, पीजी और किराये के मकानों में रहकर पढ़ते हैं। उनके माता-पिता अपनी जीवनभर की कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि राजधानी में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब शिक्षा की तलाश में निकला युवा एक ऐसी इमारत में पहुंचता है, जिसकी नींव ही नियमों और सुरक्षा के साथ समझौते पर टिकी हो, तो विकास की हमारी पूरी अवधारणा कटघरे में खड़ी हो जाती है और यह कोई पहली चेतावनी नहीं है। 2022 में भी सत्य निकेतन में निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत ढहने से दो मजदूरों की मौत हुई थी और चार लोग घायल हुए थे। उस समय भी निर्माण कार्य, सुरक्षा और भवन की निगरानी पर सवाल उठे थे। लगभग चार साल बाद उसी इलाके में फिर एक बड़ी इमारत ढह गई। इसका अर्थ है कि हमने घटना से सबक लेने के बजाय घटना को एक समाचार की तरह देखा और आगे बढ़ गए।

यहां भ्रष्टाचार की बात करते समय एक सावधानी भी जरूरी है। किसी अधिकारी या व्यवसायी को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं। लेकिन यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि नियमों के विरुद्ध निर्माण को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, निरीक्षण में लापरवाही हुई या किसी प्रकार की मिलीभगत रही, तो जिम्मेदारी केवल भवन मालिक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिसने नियम तोड़े और जिसने नियम तोड़ने दिए-दोनों की जवाबदेह बनाना होगा। सत्य निकेतन की त्रासदी को जुलाई 2024 के पुराने राजेंद्र नगर हादसे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहां राव आईएएस स्टडी सफल के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों-तनीया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन की मृत्यु हुई थी। सबसे भयावह तथ्य यह था कि बेसमेंट का उपयोग लाइब्रेरी के रूप में हो रहा था, जबकि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उसे पार्किंग और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात सामने आई-हादसे से लगभग एक महीने पहले एक विद्यार्थी ने एमसीडी में शिकायत की थी। भारत में भवन निर्माण के लिए नियमों की कमी नहीं है। नक्शा स्वीकृति, भवन उपविधियां, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा, अधिभोग प्रमाणपत्र, पार्किंग, बेसमेंट के उपयोग-हर क्षेत्र के लिए नियम हैं। लेकिन समस्या नियमों की संख्या नहीं, उनके पालन की ईमानदारी है। जब किसी भवन में एक मंजिल की अनुमति हो और चार-पांच मंजिलें खड़ी हो जाएं, जब बेसमेंट स्टोरेज के लिए स्वीकृत हो और वहां लाइब्रेरी या व्यावसायिक गतिविधि चलने लगे, जब सड़क की जलनिकासी बाधित हो और फिर भी निर्माण चलता रहे-तो सवाल केवल नागरिक की मनमानी का नहीं है। सवाल उस पूरी निगरानी व्यवस्था का है, जो आंखों के सामने होने वाले बदलाव को देखने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं करती। भ्रष्टाचार केवल रिश्तव लेने का नाम नहीं है। भ्रष्टाचार वह भी है जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्य को जानबूझकर न निभाए। किसी अवैध निर्माण को देखकर आंखें बंद कर लेना भी व्यवस्था के प्रति अपराध है। किसी भवन को जोखिमपूर्ण जानते हुए कार्रवाई न करना भी भ्रष्ट प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा है।

व्यंग्य

कसौटी पर अभी मंजिल दूर



बैडमिंटन के बड़े टूर्नामेंट्स में भारत की मजबूत उपस्थिति है, यह इस बार भी जाहिर हुआ। लेकिन सर्वोच्च सफलताओं की कसौटी पर अभी मंजिल दूर है। भारत को सिर्फ एक कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

देश ने राहत की सांस ली है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन दोपहुक्त ढंग से हुआ। इस साल के आरंभ में उसी स्टेडियम में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के आयोजन के दौरान बंदरों और कबूतरों की बार-बार घुसपैठ भारत की बदनामी की वजह बनी थी। काबिल-ए-तारीफ है कि आयोजकों ने उस अनुभव से सबक सीखा। नतीजतन, जिस समय दुनिया का ध्यान भारत पर टिका था, कोई ऐसी बात नहीं हुई, जो देशवासियों के लिए असहजता का कारण बनती।

जहां तक खेल का संबंध है, भारत ने 2011 से लगातार कोई ना कोई मेडल जीतने का सिलसिला बरकरार रखा, लेकिन कुल प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी फीका रहा। अपना माहौल होने के बावजूद भारत को सिर्फ ट्रेसी जॉली और गायत्री गोपीचंद के महिला डबल्स में जीते कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। दरअसल, दिल्ली में जाहिर यह हुआ कि बैडमिंटन जैसे बेहद प्रतिस्पर्धी खेल में किसी देश के लिए वर्चस्व बनाए रखना आसान नहीं है। पुरुष सिंगल्स में टॉप 5 सीड वाले खिलाड़ी सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गए। उधर बैटमिंटन की महाशक्ति जापान कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत सका। एक अन्य महाशक्ति चीन को सिर्फ एक स्वर्ण पदक से संतोष करना पड़ा। कुल पांच श्रेणों में हुए मुकाबलों में इंडोनेशिया किसी फाइनल में जगह नहीं बना सका। स्कैंडेनेवियन देशों- खासकर डेनमार्क की नाकामियां भी ध्यान खींचती रहीं। जबकि नई महाशक्ति के रूप में उभरता का उदय हुआ, जिसने पुलिस सिंगल्स और मिस्कड डबल्स के स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता का संदेश है कि बैडमिंटन जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाले खेल में अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए नई प्रतिभाओं के निरंतर उदय की उर्वर जमीन अनिवार्य है। इस सदी में भारत का इस खेल में एक ताकत बनना बड़ी उपलब्धि रहा है। बड़े टूर्नामेंट्स में भारत की मजबूत उपस्थिति है, यह इस बार भी जाहिर हुआ। लेकिन सर्वोच्च सफलताओं की कसौटी पर अभी मंजिल दूर है। प्रतिभाओं की खोज, खिलाड़ियों के लानुन, प्रायोजकों की मदद, और खेल के उचित माहौल के तालमेल से ही यह दूरी तय की जा सकेगी।

ब्रिक्स 2026: भारत की कूटनीतिक क्षमताओं को चुनौती देता

ब्रिक्स ग्लोबल

साउथ के हितों

को बताने और

एक ज्यादा

संतुलित

बहुध्रुवीय विश्व

बनाने के लिए

एक बुनियादी

प्लेटफ़ॉर्म बन

गया है।

ब्लॉग

डॉ. सौरभ गर्ग और डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन

अभिषेक आनंद, जोश फेल्टन और अरविंद सुब्रमण्यन ने यह पूछा है कि जिस तिमाही में ऊर्जा के क्षेत्र में जोरदार झटके लगे हों, उसमें भारत की विकास दर आखिर 7.8 प्रतिशत कैसे हो सकती है। बेशक, यह एक उचित सवाल है। इसका एक जवाब भी है और वह जवाब पिछले कुछ वर्षों से सबके सामने ही है।

समय से ही शुरुआत करते हैं। इस तिमाही की अवधि अप्रैल से जून 2026 तक थी। इससे ठीक पहले ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इजराइल के बीच का संघर्ष चरम पर पहुंच गया था। तेल की कीमतों में जोरदार उछाल आया और भारत ने इसका असर महसूस किया। हालांकि मार्च और अप्रैल के शुरुआती दिनों में इस जबरदस्त व्यवधान में कमी आई। मई आते-आते दबाव के बदल छंट गए। जून तक, मुश्किल दौर बीत चुका था। तीन महीने वाली तिमाही की शुरुआत के कुछ मुश्किल हफ्ते उस तिमाही के आंकड़ों की मनगढ़ंत नहीं बना देते।

उन महीनों के सबूत एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। ऑटोमोबाइल की बिक्री में निरंतर बढ़ोतरी हुई। एक प्रतिस्पर्धी मुद्रा की मदद से बैंक ऋण और निर्यात में बढ़ोतरी हुई। जीएसटी की दरों में कटौती के बावजूद, इसका संग्रह मजबूत बना रहा और हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में इसमें 8.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2025-26 तक के तीन वर्षों में, जीएसटी के सकल संग्रह में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 'नॉमिनल जीडीपी में 31.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये दोनों आंकड़े विल्कुल अलग-अलग क्षेत्रों से आए हैं और दोनों ही लगभग एक-दूसरे से मेल खाते हैं। जीएसटी रिटर्न कंपनियां दाखिल करती हैं। ऋण संबंधी आंकड़े बैंकों से आते हैं। व्यापार के आंकड़े बंदरगाहों से आते हैं। इनमें से कोई भी आंकड़ा सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। अर्थव्यवस्था आखिर टिकी क्यों रही? क्योंकि कई सुधारों को एक साथ अपनाया गया। वर्ष 2022-23 के बाद से केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय 65 प्रतिशत बढ़ा है और इस वर्ष इसमें 11.5 प्रतिशत और बढ़ोतरी का बजट रखा गया है। एक दशक में बनाई गई सड़कें, बंदरगाहें और बिजली संयंत्र तेल के महंगे होने पर उभ्य नहीं पड़े। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने अनौपचारिक गतिविधियों के एक बड़े हिस्से को औपचारिक बनाया और उन्हें मापी जा सकने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। दिवाला संहिता ने बूढ़े हुए कर्ज (बैड डेट) से निपटने के बैंकों और कंपनियों के तौर-तरीकों को बदल दिया। रियल एस्टेट कानून ने उस सेक्टर को साफ-सुधरा बनाया, जो कभी अटकी हुई परियोजनाओं और पैसے के अपारदर्शी लेन-देन के



लिए जाना जाता था। 'द इकोनॉमिस्ट ने 2023 में उस सफाई अभियान का उल्लेख किया था। उसने नई दिल्ली पर कोई मेहरबानी नहीं की थी।

इसके बाद, तेल की कीमतों में अचानक आए उछाल से निपटने के लिए सरकार ने जो कुछ किया, वह भी सामने है। उसने कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बोझ आम परिवारों और कंपनियों पर नहीं डाला। उसने इसकी लागत खुद वहन की। राजकोषीय गुंजाइश (फिस्कल स्पेस) का उद्देश्य ही यही है और भारत ने इसे तैयार किया है। इसका सबूत 2 सितंबर को मिला। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बीबीबी+ से बढ़ाकर ए- कर दिया और इसके साथ ही स्थिर संभावना भी जताई। इसके अलावा, देश की रेटिंग सीमा (क्रेदी सीलिंग) को भी ए कर दिया। भारत को तीन दशकों से अधिक समय से 'ए' रेटिंग नहीं मिली है। एजेंसी ने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, जीएसटी, दिवाला संहिता और सकल गैर-निष्पादित ऋण अनुपात (ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग लोन रेश्यो) के 1.8 प्रतिशत तक कम होने का उल्लेख किया। उसने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार ने उच्च पूंजीगत व्यय को जारी रखते हुए भी अपने राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2025 में जीडीपी के 4.7 प्रतिशत से घटाकर वित्तीय 2026 में 4.4 प्रतिशत कर लिया। टोक्यो स्थित एक रेटिंग समिति के लिए दिल्ली में किसी को खुश करने की कोई वकालत नहीं है। उन्होंने भी उन्हीं सुधारों को देखा और वही नतीजा निकाला।

अब आलोचना के मुख्य बिंदु पर आते हैं। लेखकाण पूछते हैं कि अगर आज ये संकेतक 7.8 प्रतिशत की विकास दर को सही ठहराते हैं, तो पूर्व के वर्षों में वैसी ही विकास दर कमजोर संकेतकों के साथ क्यों संभव हुई थी? यह मान लेना कि विकास हमेशा एक जैसी चीजों से ही

पार्टनर के तौर पर शामिल हुए, जिससे एग्रेजमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क बना। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एन डी बी) की उपलब्धियाँ: एन डी बी ने हाल ही में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और सरस्टेनेबल डेवलपमेंट में 120 से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया गया। इसने ग्लोबल साउथ को पार्टनरशिप, सांवेर्नेटी और शेयर्ड प्रायोरीटीज़ पर बना एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक सफलतापूर्वक दिया है, न कि वेस्टर्न-लेड फाइर्नेशियल इंस्टीट्यूशन्स से जुड़ी कंडीशनैलिटीज़ पर। इंड्रा-ब्रिक्स ट्रेड ग्रोथ: मेंबर्स के बीच दो दशकों के ट्रेड एक्सपेंशन ने डेवलप हो रहे इकोनॉमिक संबंधों को सामने लाया है, जिससे साउथ-साउथ ट्रेड के नए, रेसिलिएंट पेटर्न बने हैं जो बाहरी झटकों से कम वल्नेरबल हैं। कॉमर्स सेक्टरटी राजेश अग्रवाल ने 5 सितंबर, 2026 को कहा कि इंड्रा-ब्रिक्स मर्चेंडाइज़ ट्रेड अब कई गुना बढ़ गया है, जो मेंबर देशों के बीच गहरे ट्रेड इंटीग्रेशन और मजबूत इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अटनैटड पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। 2003 में \$84 बिलियन से 2024 में \$1.17 ट्रिलियन तक इंड्रा-ब्रिक्स मर्चेंडाइज़ ट्रेड 13 गुना बढ़ गया, जो 13.3 परसेंट की सालाना एवरेज रेट से बढ़ रहा है, जो इसी समय के दौरान 5.7 परसेंट की ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ से काफी ज़्यादा है। भारत के लिए अलग-अलग चुनौतियों के बीच ब्रिक्स को आगे ले जाना आसान नहीं होगा। उनमें से कुछ ये हैं: ब्रिक्स कनेक्ट्स को लागू करना: भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की पहल 'ब्रिक्स कनेक्ट्स' का उद्देश्य सदस्य देशों के नागरिकों को लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता देना है। इसके मुख्य फ़ोकस एरिया में डिजिटल पेमेंट और फ़ाइनैशियल इनक्लूज़न (वित्तीय समावेश) को बढ़ाना, एजुकेशनल डिग्री को आपसी मान्यता देना, सस्ता इंटरनेट और ईसानों पर केंद्रित ए आई, एक नया ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब, और बेहतर ट्रेड कॉरिडोर शामिल हैं, जिनसे लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो सकती है और सामान सस्ता हो सकता है। अंदरूनी सोच में विभिन्नता: यह ग्रुप एक जैसा ग्रुप नहीं है, जिससे आम सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। इसमें बहुत अलग-अलग जियोपॉलिटिकल सोच वाले देश हैं, जिनमें वे देश शामिल हैं जो पश्चिम का सक्रिय रूप से सामना कर रहे हैं (जैसे,

रूस, ईरान) से लेकर वे देश भी शामिल हैं जो पश्चिमी देशों (जैसे, भारत, ब्राज़ील) के साथ मज़बूत स्ट्रेटेंजक और इकोनॉमिक संबंध बनाए हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल एकता बनाना विस्तार: ब्रिक्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह खुद को ज़्यादा बढ़ाए बिना अपनी बढ़ती जियोपॉलिटिकल अहमियत को ठोस इंस्टीट्यूशनल असर में बदले। तेज़ी से विस्तार से इस ग्रुप के बेकाबू होने और निर्णायक रूप से काम करने की इसकी क्षमता कम होने का खतरा है। अलग-अलग इकोनॉमिक प्राथमिकताएँ: फाइर्नेशियल इंटीग्रेशन पर सदस्यों के अलग-अलग विचार हैं। जहां कुछ लोग वेस्ट से तेज़ी से फाइर्नेशियल डीकपलिंग पर जोर देते हैं, वहीं दूसरे प्रैक्टिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशियल बदलावों के नतीजों से डरते हैं। ब्रिक्स उस पश्चिमी नैरेटिव को बेअसर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है जिसके तहत इसे 'पश्चिम-विरोधी क्लब' या एक विघटनकारी ताकत के तौर पर देखा जाता है। इन कोशिशों से निपटने के लिए यह कई रणनीतियाँ अपनाता है: नैरेटिव को नए सिरे से पेश करना: 2026 में भारत की अध्यक्षता में नेतुत्व ने टकराव वाली छवि को स्पष्ट रूप से खारिज किया है। आधिकारिक राजनयिक रुख इस बात पर जोर देता है कि रब्रिक्स पश्चिम-विरोधी नहीं है; यह संतुलन का पक्षधर हैर और 'ब्रिक्स देशों को G7-विरोधी नहीं बनाना चाहिए, और G7 को ब्रिक्स -विरोधी नहीं बनना चाहिए।' यह समूह खुद को स्वाभाविक रूप से विरोधी के बजाय 'गैर-पश्चिमी' और सुधारवादी के तौर पर पेश करता है। डी-डॉलरलाइज़ेशन पर व्यावहारिक और क्रमिक दृष्टिकोण: गंभीर आर्थिक जवाबी कार्रवाई (जैसे टैरिफ की धमकियाँ) से बचने के लिए, ब्रिक्स ने डी-डॉलरलाइज़ेशन से जुड़ी अपनी बयानबाजी को नरम किया है। अमेरिकी डॉलर या ब्रिक्स की साझा मुद्रा को अचानक और पूरी तरह से बदलने के बजाय—जिसका भारत जैसे सदस्यों ने स्पष्ट रूप से विरोध किया है—यह समूह व्यावहारिक और क्रमिक बदलाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें स्थानीय मुद्रा में लेन-देन को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय स्वीप समझौते और व्यापार के लिए डिजिटल मुद्रा के ढांचे की संभावनाओं को तलाशना शामिल है।

विकास के आंकड़ों की जांच-परख



संभव होती है, जरूरी नहीं है। निर्यात और औपचारिक ऋण से प्रेरित तिमाही, घरेलू खर्च या सरकारी निवेश से चलने वाले वर्ष जैसी नहीं होगी। पूर्व के वर्षों में विकास के अपने कारण थे, जो उस समय साफ दिख रहे थे। वर्ष 2024-25 तक, शेयर बाजार तेजी से चढ़ा और अधिक संख्या में भारतीयों ने निवेश करना शुरू किया। वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच परिवारों की शुद्ध वित्तीय वचत में 60 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई। गैर-बैंक और तकनीक-आधारित ऋणदाता तेजी से बढ़े। वाणिज्यिक क्षेत्र में कुल संसाधनों का प्रवाह तीन वर्षों में 72 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें गैर-बैंकों की हिस्सेदारी 96 प्रतिशत बढ़ी। ये असली कारण थे। बस, वे अलग थे।

मार्च 2023 से मार्च 2026 के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए गए बकाया ऋण में 66.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जुलाई 2026 में भी यह बढ़ोतरी लगभग 25 प्रतिशत की दर से जारी थी। ऐसा कहा जाता है कि ऊर्जा की कीमतों में अचानक उछाल से छोटी कंपनियों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। लेकिन उन्हें ऋण देने वाले इस बात से सहमत नहीं दिखते। ऋणदाता आम तौर पर उन कंपनियों को ऋण नहीं देते, जिनके असफल होने की आशंका होती है।

लेखकों के तर्क की तह में यह बात छिपी है कि सांख्यिकी मंत्रालय का काम सरकार की छवि को बेहतर दिखाना है। लेकिन आंकड़े इस बात की पुष्टि नहीं करते। वर्ष 2023-24 के लिए, मंत्रालय ने विकास दर के अनुमान को 9.2 प्रतिशत (पुरानी श्रृंखला के तहत) से घटाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया था। यानी, उन्होंने खुद ही लगभग दो प्रतिशत अंक कम कर दिए। अन्य आरोपों के मामले में भी गणित खिलाफ जाता है।

वर्ष 2024-25 में, नई श्रृंखला के तहत



'इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा...', आगरा में अजन्मे की मौत पर अखिलेश यादव की पोस्ट, जो हो रही वायरल

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। सिस्टम की सुस्ती और प्रशासनिक लापरवाही ने 2 सितंबर को गढ़वार गांव के एक अजन्मे की ज़िंदगी छीन ली थी। सड़क के गड्ढे में एंबुलेंस फंसने से प्रसूता निधि समय से अस्पताल नहीं पहुंच सकी थी। नतीजतन गर्भ में ही नवजात की मौत हो गई थी। सोमवार रात सपा मुखिया अखिलेश यादव की फेसबुक पोस्ट 'इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से वो भी मारे जा रहे हैं, जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया है' ने हलचल बढ़ा दी है।

गढ़वार गांव के भानु प्रताप सिंह, विभूत नरायन सिंह, रिक्की सिंह, अमित कुमार, हरेद्र सिंह आदि शनिवार को समाधान दिवस में दर्ज कराई शिकायत में कहा था कि 2 सितंबर की रात गढ़वार गांव



के प्रवेंद्र की पत्नी निधि को प्रसव पीड़ा हुई थी। रात 1 बजे परिजन ने कॉल कर एंबुलेंस बुलाई थी। कुछ देर में ही पहुंची एंबुलेंस गांव के मुख्य मार्ग पर बने गड्ढे में फंस गई थी। दावा किया कि ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से करीब दो घंटे तक मशक्कत कर एंबुलेंस को बाहर निकाला था। इसके बाद

परिजन प्रसूता को लेकर पहले जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, फिर बाह के निजी अस्पताल ले गए।

परिजन ने दावा किया था कि डॉक्टर ने प्रसव में देरी के कारण नवजात की मौत हो गई। मंगलवार को जैतपुर के अधीक्षक डॉ. दीपक यादव, बाह के अधीक्षक डॉ. जितेंद्र

वर्मा मृतक नवजात के घर पर पहुंचे। मृतक नवजात के पिता का बयान दर्ज किया। उसके बाद बाह के एसडीएम विनोद कुमार पहुंचे। उन्होंने पूछताछ के बाद दावा किया कि बारिश से क्षतिग्रस्त पुराने संपर्क मार्ग पर एंबुलेंस को महज 15-20 मिनट के विलंब पर प्रसूता को सुरक्षित जैतपुर के सामुदायिक

किशोरी के साथ किया सामूहिक दुराचार

जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार देर रात किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पीड़िता की मां के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 10:30 बजे किशोरी ने पेट में दर्द होने की बात कही और घर से करीब 50 मीटर दूर स्थित शौचालय चली गई। आरोप है कि शौचालय से बाहर निकलते ही पहले से घात लगाए तीन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पास के मकई के खेत में खींच ले गए। वहां आरोपियों ने किशोरी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके साथ सामूहिक दुराचार किया।परिजनों के मुताबिक, किशोरी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां की नींद खुल गई। मां जब मौके की ओर पहुंची तो आरोपी किशोरी को खेत से बाहर फेंककर फरार हो गए। इसके बाद परिजनों ने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी।

एक महीने से था गायब, अचानक आया और पत्नी को मार डाला... फिर दोनों बच्चों को लेकर भागा पति, कहानी किरण हत्याकांड की

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। ताजनगरी आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र स्थित पीलीपोखर गांव में एक ऐसा जघन्य हत्याकांड सामने आया है, जिसने रिश्ते की पवित्रता और पारिवारिक ताने-बाने को तार-तार कर दिया है। एक महीने से घर से गायब चल रहे बेरोजगार पति ने अचानक लौटकर पत्नी के सिर पर भारी वस्तु से हमला किया और फिर बर्बता की हद्दें पार करते हुए चाकू से उसका गला रेत दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने दोनों मासूम बच्चों को साथ लेकर मौके से फरार हो गया। पीलीपोखर निवासी राजकुमार सिकरवार का 32 वर्षीय बेटा विवेक सिकरवार कोई कामकाज नहीं करता था। उसकी शादी करीब 8 साल पहले एम्मादपुर के गांव चली निवासी विनोद सिंह की बेटी किरण (30 वर्ष) के साथ हुई थी। दोनों के दो छोटे-छोटे



बेटे हैं, लक्ष्य (5 वर्ष) और चुन्नु (3 वर्ष)। मायके वालों और पड़ोसियों के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज की अनवरत मांगों को लेकर विवेक और उसके घरवाले किरण को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे।

किरण के भाई ललित ने पुलिस को दिए बयान में रोते हुए बताया कि उसकी बहन को खूबहाली के लिए कई बार दोनों परिवारों और गांव के संश्रुत लोगों के बीच पंचायतें बुलाई गईं। हर बार आरोपी समझौता कर लेता था, लेकिन घर पहुंचते ही फिर से मारपीट और विवाद का सिलसिला शुरू हो जाता था। विवेक कोई काम-धंधा नहीं

निजी अस्पताल पहुंचे एसीएमओ, संचालन पर लगाई रोक

गढ़वार की निधि को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर से परिजन अपनी इच्छा से बाह

के श्याम जी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। निधि का प्रसव श्याम जी हॉस्पिटल में ही हुआ था। एसीएमओ डॉ. सुशील कुमार ने अस्पताल की जांच की। अभिलेख मांगे, अलमारी की चाबी न होने की वजह से संचालक ने अभिलेख दिखाने में असमर्थता जताई। एसीएमओ ने बताया कि अस्पताल पंजीकृत तो है, लेकिन संचालक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। नतीजतन अभिलेख उपलब्ध कराने तक अस्पताल के संचालन को बंद रखने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में निधि के प्रसव की पुष्टि हुई है। नवजात की मौत की वजह की जांच हो रही है। जांच के बाद असल वजह सामने आ सकेगी।

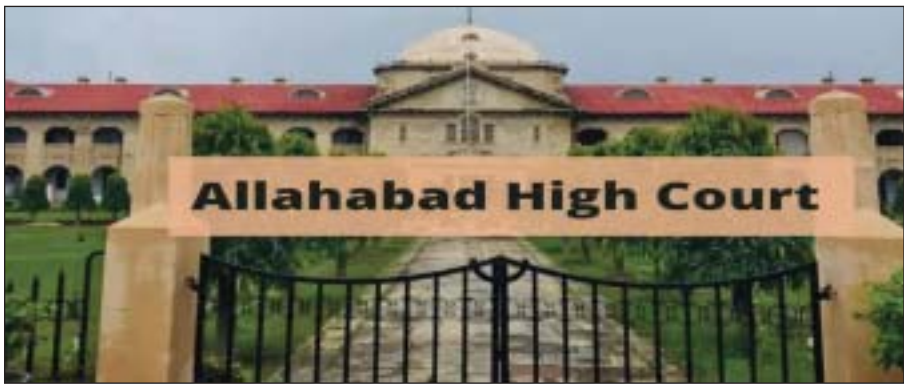
स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया था। मौजूद चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ ने प्रसूता को भर्ती किया था। प्रारंभिक परीक्षण में जच्चा बच्चा की स्थिति सामान्य पाई गई थी।

चिकित्सीय निगरानी में रखा गया था। सुबह 5 बजे परिजन प्रसूता स्वेच्छा से बाह के निजी

चिकित्सालय ले गए थे। प्रसव में

नवजात बच नहीं सका था। उन्होंने किसी भी स्तर पर चिकित्सीय उपेक्षा या घंटों तक मार्ग अवरुद्ध होने की बात के दावे को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए संपर्क मार्ग को लोक निर्माण विभाग ने दुरुस्त करा दिया है। प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित की गई है।

किराये के मकान में दुर्घटनावश मौत पर मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आपराधिक कार्रवाई रद्द



पहुंचने पर छात्र का शव मकान के बाथरूम में मिला था। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि बाथरूम में गैस गीजर लगा था और पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं था। ऐसे में आशंका जताई गई कि गीजर से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण छात्र को मौत हुई। जांच के बाद पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ लापरवाही से मौत मामले में चार्जशीट दाखिल

कर दी। ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान/समन आदेश जारी किया तो याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सिर्फ अंदाजे पर आपराधिक केस नहीं चल सकता

कोर्ट ने कहा कि छात्र की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मकान में केवल मौत होने से बीएनएस की धारा-106 के तहत मालिक को

जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि गीजर सुरक्षा मानकों के खिलाफ लगाया गया था, वह खराब था। इसकी जानकारी मकान मालिक को थी या पहले कभी लीकेज की शिकायत के बाद भी उसने ठीक नहीं कराया। केवल अंदाजे पर आपराधिक केस नहीं चल सकता। ऐसे में कोर्ट ने आपराधिक की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी।

वृद्धाश्रम का निरीक्षण, समस्याओं पर पूछताछ

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार शर्मा के निर्देशन व सचिव, सुशील कुमार सिंह व जिला प्रोबेशन अधिकारी, विजय कुमार पाण्डेय के द्वारा “निःशुल्क वृद्धजन आवास वृद्धाश्रम सैयद अलीपुर सदर का औचक निरीक्षण व वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा वृद्धाआश्रम में रह रहे वृद्धजनों से वार्ता की गई व उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ की गई। सभी वृद्धजनों द्वारा आश्रम में कोई समस्या नहीं बताई गई। साफ-सफाई को लेकर उचित दिशा-निर्देश दिया गया। तत्पश्चात विधिक साक्षरताथ जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। स्विगल जज द्वारा बालक वृद्ध एवं वयस्क का अंतर बताते हुए बताया कि माता-पिता के

भरण पोषण का भार वयस्क पुत्र पुत्री उनकी अनुपस्थिति में पौत्र और पौत्री एवं दत्तक पुत्र का होता है यदि कोई परेशानी भोजन वस्त्र आवास रहन-सहन मनोरंजन एवं आपातकालीन परेशानी में हो तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें अन्यथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दें उन्होंने भरण पोषण की प्रक्रिया को सरल बताते हुए कहा कि एक आवेदन पत्र पर त्वरित रूप से इसका निस्तारण 90 दिन में हो जाता है अधिक से अधिक 30 दिन उसमें और बढ़ाया जा सकता है जिला प्रोबेशन ने कहा कि वृद्ध आश्रम में आरामदायक कमरे नियमित पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य देखभाल मनोरंजन की निशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार को करनी पड़ती है यह देश के संविधान द्वारा भी वर्णित है और आपात सेवा परामर्श और पुनर्वास को व्यवस्था होती है।

बीएसए ने किया स्कूलों का निरीक्षण, दिया निर्देश

जौनपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने बुधवार को विकासखंड बक्शा एवं महाराजगंज क्षेत्र के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था, छात्र उपस्थिति, साफ-सफाई, शौचालय व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया तथा निर्देश दिए।बीएसए ने कंपोजिट विद्यालय सार्याबागर, बक्शा का निरीक्षण किया। विद्यालय परिसर एवं शौचालयों में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय गडेरिया, महाराजगंज का निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय पहेरीपुर, महाराजगंज की भी समस्त स्टाफ उपस्थित मिला। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की छत की मरम्मत की आवश्यकता सामने आने पर बीएसए ने मौके से ही जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) से वार्ता कर मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।



एक तरफा तो नहीं होता जा रहा आपका रिश्ता, इन 5 संकेतों से पहचानें



रिश्ते में लड़ाई नहीं है फिर भी कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं कि दो लोग साथ होते हुए भी दूर होते जाते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता है और हम रिश्ते को एक तरफा छो रहे होते हैं। ये बदलाव बस चुपचाप आता है। ज्यादातर कपल को ये बात बहुत मामूली महसूस होती है, लेकिन समय के साथ आपको खुशी की जगह उस रिश्ते में थकान जैसी महसूस होने लगती है। मानो सिर्फ आप ही सारी चीजों को अपने कंधे पर ढो रहे हैं और पार्टनर का कोई एफर्ट ही नहीं

है। इस आर्टिकल में जानेंगे ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका रिश्ता अब बस एक तरफा होता जा रहा है।

हर रिश्ता किसी लड़ाई या फिर धोखे की वजह से नहीं टूटता है, बल्कि कई बार वो इसलिए टूट जाता है क्योंकि उसमें सारे एफर्ट बस एक ही पार्टनर के होते हैं। 5 ऐसे मामूली से लगने वाले संकेत हैं जो ये बताते हैं कि आप एक तरफा रिश्ते की जबरदस्ती आगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं।

आप ही करते हैं हमेशा पहल

आपके रिश्ते में भी ऐसा है कि पहले आप दोनों मिलकर घूमने का प्लान किया करते थे और आपके पार्टनर भी मैसेज कॉल पर जुड़े रहते थे, लेकिन अब आप ही पहले मैसेज करते हैं, प्लान बनाते हैं और पता करते हैं कि वे कब फ्री हैं। ऐसे में कई बार एहसास भी नहीं होता है कि कैसे आप ही उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं।

क्या आपको ही रहती है चिंता?

आपको उनके काम के स्ट्रेस, उनसे जुड़ी हर छोटी-मोटी चिंताएं याद रहती हैं और आप हमेशा उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी पूछते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ऐसे में ये चीज दिखाती है कि दिलचस्पी सिर्फ एक तरफा चल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर पर बहुत काम का बोझ या जिम्मेदारियां हों, इसलिए एक बार आपको इस पर खुलकर बात करनी चाहिए।

हमेशा आप ही खत्म करते हैं लड़ाई

पति-पत्नी या लव पार्टनर्स का रिश्ता हमेशा ही ऐसा होता है, जिसमें नोक-झोंक भी खूब होती है, लेकिन दोनों तरफ से इस झगड़े को खत्म करना। गुस्सा हुए पार्टनर को मनाना यही तो रिश्ते की खूबसूरती होती है। अगर आपका रिश्ता ऐसा होता जा रहा है कि हारकर आप ही हमेशा लड़ाई को खत्म करते हैं तो ये एकतरफा एफर्ट का संकेत है।

आप अकेलापन महसूस करते हैं

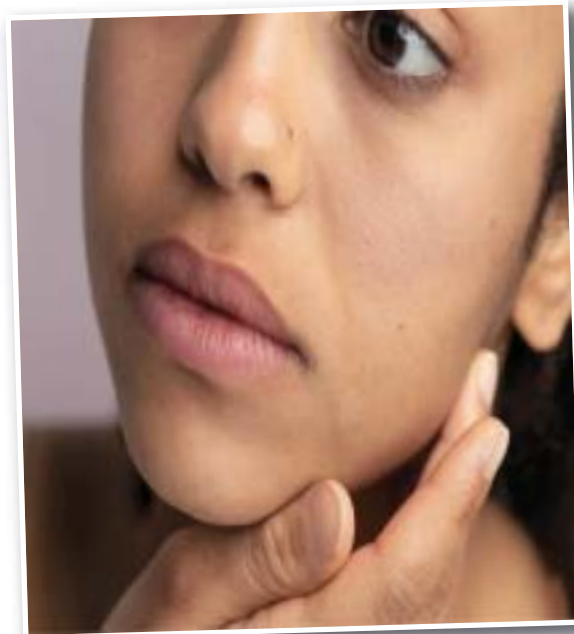
किसी भी रिश्ते में अगर एक पार्टनर हमेशा एफर्ट लगाए तो उसे धीरे-धीरे अकेलापन महसूस होने लगता है और वो सिर्फ उस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ सहता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप पार्टनर के साथ होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं तो हो सकता है रिश्ता एक तरफा होता जा रहा है।

समझीते तो नहीं कर रहे आप

अगर आपके रिश्ते में भी चीजें इस तरह से चल रही हैं कि आपको अपनी पसंद-नापसंद को लेकर समझौता करना पड़ता है तो हो सकता है कि रिश्ता एक तरफा होता जा रहा हो। जैसे उनके शेड्यूल के हिसाब से प्लान बदल जाता है, जबकि आपका कहीं जाने का बहुत मन था।

चेहरे की चमक होगी दोगुनी, पुराने जमाने के ये घरेलू नुस्खे हैं त्वचा के लिए कमाल

स्किन केयर के दादी-नानी नुस्खे काफी कारगर माने जाते हैं। इसमें साइड इफेक्ट होने की संभावना भी नहीं होती है। चलिए जानते हैं पुराने जमाने में त्वचा की देखभाल में यूज की जाने वाली चीजों के बारे में।



त्वचा की देखभाल के लिए बाजार में आपको हजारों रुपये में बिकने वाले प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो वहीं कई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी मौजूद हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया स्कॉल करते वक़्त न जाने कितनी रील हमारे सामने आती हैं, जिसमें DIY स्किन केयर के टिप्स दिए होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों से साइड इफेक्ट होने का डर भी रहता है। पुराने जमाने में जब ये सारी चीजें इतनी पॉपुलर नहीं थीं तो तब लोग अपनी त्वचा की देखभाल में नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। आप आज के समय में भी इन चीजों को अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

खराब लाइफस्टाइल की वजह से सेहत के साथ ही त्वचा पर भी बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ आज के समय में पॉल्यूशन और केमिकल वाले प्रोडक्ट भी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि लोग दोबारा से नेचुरल और हर्बल चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें लोग त्वचा की देखभाल में पुराने जमाने में यूज किया करते थे।

मुल्तानी मिट्टी का लेप

पहले के समय में त्वचा के साथ ही बालों की देखभाल में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल काफी किया करते थे। ये आपकी त्वचा को मुलायम बनाती है और सनबर्न से लाल होने वाली स्किन को भी सुदिंग इफेक्ट देती है। गर्मी के मौसम में मुल्तानी मिट्टी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद रहती है। इसे पानी में भिगीकर रख दें या फिर पाउडर बनाकर तुरंत गुलाबजल के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं।

हल्दी और बेसन का उबटन

पहले के समय में लोग उबटन का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया करते थे। इसके लिए लोग हल्दी को पीसकर उसमें बेसन, नारियल या सरसों का तेल मिलाया करते थे। इसके बाद इसे पूरे शरीर पर लगाकर मसाज की जाती है, जिससे त्वचा गहराई से साफ होती है और स्किन को नमी भी मिलती है। हल्दी आपकी त्वचा की रंगत को निखारती है तो वहीं बेसन एक्सफोलिएशन (डेड स्किन हटाने) का काम करता है।

असली चंदन का लेप

पहले के समय में लोग त्वचा के लिए चंदन का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया करते थे। आज मार्केट में चंदन पाउडर मिल जाता है, लेकिन पुराने जमाने में असली चंदन की लकड़ी को घिसकर इसका त्वचा पर लेप लगाया जाता था। ये आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। अगर स्ट्रेस और गर्मी की वजह से सिरदर्द हो तो भी चंदन का लेप तुरंत राहत दिलाता है।

तेल की देते थे तरजीह

पहले के लोग मॉइश्चराइजर का यूज नहीं करते थे। इसकी जगह वो अपनी त्वचा पर तेल से मसाज किया करते थे, जिससे स्किन को न सिर्फ नमी मिलती थी, बल्कि पोषण भी मिलता था। लोग आयुर्वेद आधारित कुमकुमादी तैलम का इस्तेमाल करते थे जो त्वचा की कई समस्याओं से निजात दिलाता है और स्किन को चमकदार बनाता है।

दूध की मलाई का होता था यूज

पहले के समय में लोग दूध की मलाई भी स्किन केयर में इस्तेमाल करते थे। मलाई में चुटकीभर हल्दी मिलाकर चेहरे और हाथ-पैरों की त्वचा पर लगाएं। कुछ देर के बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे क्लीन कर लें और चेहरे को सादा पानी से वांश करें। खासकर ये रूखी त्वचा वालों के लिए काफी बढ़िया रेमेडी है।



मेकअप के दौरान कलर करेक्टर का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां



कलर करेक्टर का इस्तेमाल मेकअप को बेहतरीन बनाने में मदद करता है। यह त्वचा की असमानताओं को छिपाने और एक समान रंग देने में सहायक होता है। हालांकि, कई महिलाएं कलर करेक्टर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पातीं और इससे उनका मेकअप बिगड़ जाता है। इस लेख में हम आपको 5 आम गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें महिलाएं कलर करेक्टर का

इस्तेमाल करते समय करती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।

गलत रंग का चयन करना

कलर करेक्टर का सही रंग चुनना बहुत जरूरी होता है। कई महिलाएं अपने त्वचा के रंग को ध्यान में रखे बिना ही किसी भी रंग का चयन कर लेती हैं, जिससे उनका मेकअप अच्छा नहीं दिखता।

उदाहरण के लिए, अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो पीच या नारंगी शेड बेहतर होते हैं, जबकि गहरे त्वचा रंग वाली महिलाओं के लिए हरा या पीला शेड उपयुक्त होते हैं।

सही रंग चुनने से आपका मेकअप ज्यादा निखरता है।

ज्यादा मात्रा में उपयोग करना

कलर करेक्टर का ज्यादा उपयोग करना एक बड़ी गलती हो सकती है। कुछ महिलाएं यह सोचती हैं कि ज्यादा मात्रा में कलर करेक्टर लगाने से उनकी समस्याएं बेहतर तरीके से छिपेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता।

ज्यादा मात्रा में कलर करेक्टर लगाने से चेहरा भारी दिखने लगता है और प्राकृतिक रूप से छिपी हुई समस्याएं उभरकर सामने आने लगती हैं।

इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में ही कलर करेक्टर का उपयोग करें, ताकि आपका मेकअप स्वाभाविक लगे।

गलत जगह पर लगाना

कलर करेक्टर लगाने की जगह भी अहम होती है।

कई महिलाएं बिना सोचे-समझे कहीं भी कलर करेक्टर लगा लेती हैं, जिससे उनका पूरा लुक बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो वहां पीच या नारंगी शेड लगाएं, ताकि वे छिप जाएं।

इसी तरह अगर आपकी त्वचा पर लाल धब्बे हैं तो उन्हें छिपाने के लिए सही जगह पर सही रंग का उपयोग करें।

गलत तरीके से मिलाना

कलर करेक्टर को सही तरीके से मिलाना बहुत जरूरी होता है, ताकि वह त्वचा में पूरी तरह मिल जाए और अलग से दिखाई न दे। कई महिलाएं इसे ठीक से नहीं मिलतीं, जिससे उनका मेकअप बनावटी लगता है। सही तरीके से मिलाने के लिए पहले उंगलियों या स्पंज की मदद से हल्के हाथों से फैलाएं, फिर ब्रश की मदद से सेट करें।

इससे आपका मेकअप प्राकृतिक दिखेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा।

बेस मेकअप के साथ मेल न खाना

कलर करेक्टर और बेस मेकअप का मेल होना चाहिए, ताकि आपका चेहरा एक समान दिखे। कई बार महिलाएं अलग-अलग ब्रांड या शेड का उपयोग कर लेती हैं, जिससे उनका चेहरा असंगत दिखता है।

हमेशा एक ही ब्रांड और शेड का उपयोग करें, ताकि आपका मेकअप पूरी तरह संतुलित लगे।

इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने मेकअप को बेहतरीन बना सकती हैं और हर मौके पर खूबसूरत दिख सकती हैं।

दुनिया के सबसे बड़े डायमंड बोर्स पहुंचे बेल्जियम के प्रधानमंत्री, 100 साल पुरानी हीरा साझेदारी में नया मील का पत्थर



नाइजर जेट की बढ़ती दौलत हूए कहां
कि भारत को यूटीए फाइटर बेचना
राष्ट्रपति पुतिन के एजेंडे में सबसे
ऊपर है। साथ ही माँको, Su-57
उपनौलार्जी को साझा करने की
संभावना को ईदिल्ली के साथ
लगातार बातचीत कर रहा है।
क्रैमानि के प्रवक्ता दिमित्री
पेस्कोव ने कहा, “Su-57 जेट बहुत
एवॉलंसड मशीन है और ये दुनिया की
बेहतरीन मशीनों में से एक है। इन
मशीनों को बेचना (पुतिन की ब्रिक्स
प्रक्षीय बैठक के) एजेंडे में शामिल
है।”



गरबा पर सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता ने बीजेपी नेताओं से अलग लिया स्टैंड, कहा- मुस्लिमों की एंट्री से दिक्कत नहीं

>> नवरात्रि से पहले गरबा पर सियासी संग्राम! >> गरबा में मुस्लिमों की एंट्री गलत नहीं-अमृता

मुंबई, एजेंसी। नवरात्रि से पहले महाराष्ट्र में गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं और विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों के रुख के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का बयान चर्चा का विषय बन गया है। गरबा में प्रवेश को लेकर कुछ भाजपा नेताओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से सख्त नियम लागू करने की मांग की जा रही है। कहीं पहचान की जांच तो कहीं माथे पर तिलक लगाकर प्रवेश देने जैसे सुझाव सामने आ रहे हैं। ऐसे में चंद्रपुर में अमृता फडणवीस ने भारतीय त्योहारों



की सर्वसमावेशी परंपरा का उल्लेख करते हुए अलग राय रखी। अमृता फडणवीस ने कहा कि भारतीय पर्व सभी को साथ लेकर चलने वाली परंपरा का हिस्सा हैं। उनके मुताबिक, यदि कोई मुस्लिम

व्यक्ति गरबा उत्सव में शामिल होता है, आयोजन के नियमों का पालन करता है और उत्सव का आनंद लेता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनके इस बयान के बाद गरबा में मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर चल

रही राजनीतिक बहस ने नया मोड़ ले लिया है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि पिछले वर्षों में नवरात्रि के दौरान इसी मुद्दे पर कई हिंदुत्ववादी संगठनों और नेताओं ने गैर-हिंदुओं के प्रवेश का विरोध किया है।

अब अमृता फडणवीस के बयान ने भाजपा और उससे जुड़े संगठनों के भीतर इस विषय पर अलग-अलग सोच होने की चर्चा को हवा दे दी है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर सवाल उठा सकता है कि जब मुख्यमंत्री परिवार की ओर से सर्वसमावेशी सोच की बात की जा रही है, तो फिर गरबा में एंट्री को लेकर हर साल विवाद क्यों खड़ा होता है।

पंडालों के लिए VHP की गाइडलाइन

नवरात्रि से पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि गरबा में प्रवेश को

लेकर भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों का अंतिम रुख क्या रहता है और क्या अमृता फडणवीस के बयान के बाद इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी में कोई बदलाव आता है। बता दें कि नितेश राणे ने गरबा में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की बात कही थी। वीएचपी ने पंडालों के लिए गाइडलाइन भी जारी की। विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों की एंट्री रोकने के लिए आने वाले लोगों से तिलक लगाकर आने और आधार कार्ड लाने की अपील की है। उद्धव गुट, शरद गुट और कांग्रेस ने VHP की गाइडलाइंस की कड़ी आलोचना की है।

भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक सीएनआर राव को SIR का नोटिस, पहचान साबित करने को कहा गया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत रत्न से सम्मानित देश के सबसे प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव अब अपनी ही पहचान साबित करने के लिए सुनवाई में पेश होने को मजबूर हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके नाम में कुछ गलती पाई गई है, जिसके करेक्शन के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। पुराने रिकॉर्ड में उनका नाम प्रोफेसर सीएनआर राव (Prof. C.N.R.Rao) है।

मगर मौजूदा रिकॉर्ड में उनके अंग्रेजी नाम में एक एक्सट्रा 't' जुड़ गया है। इसके बाद उनका नाम 'Proffl' CNR Rao' हो गया है। इस कारण अब उन्हें यह नोटिस दिया गया है कि वे आकर साबित करें कि वे वाकई वही प्रोफेसर सीएनआर राव हैं, जिनका जन्म बेंगलुरु के बसवनगुडी में हुआ, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनगिनत योगदान दिए

और जिन्हें 2014 में भारत रत्न अवार्ड मिला। प्रोफेसर राव को मल्लेश्वरम में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक, उनके परिचितों को इस नोटिस की खबर नहीं थी। जब उनके लोगों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि प्रोफेसर राव की तबीयत ठीक नहीं है। वे फोन बहुत कम चलाते हैं और ईमेल खुद कभी चेक नहीं करते। SIR के दौरान भरे गए फॉर्म में गलतियों की वजह से 43 लाख से ज्यादा वोटों को नोटिस भेजा गया है। यह लिस्ट अब सबके लिए उपलब्ध है। 'सेल्फ-मिसमैच' का मतलब है एक तरह की गड़बड़ी। जब कोई वोटर जो 2002 की वोट लिस्ट में था, SIR फॉर्म भरते समय 2002 वाली जानकारी डालता है, लेकिन वह जानकारी आज की लिस्ट से मेल नहीं खाती।

सीरीज शक की रिलीज तारीख आई, लापता बच्चे की तलाश भटकती दिखेंगी परिणीति चोपड़ा



परिणीति चोपड़ा एक बार फिर ओटीटी पर वापसी के लिए तैयार हैं। उनकी नई मिस्ट्री-थ्रिलर सीरीज ‘शक : ट्रस्ट नो वन’ का पोस्टर और रिलीज डेट सामने आ गई है। 124 सितंबर 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली इस सीरीज में एक मां अपने नौ साल से लापता बच्चे की तलाश करती नजर आएगी, लेकिन इस खोज के दौरान कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आएंगे।

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा एक बार फिर डिजिटल मंच पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी रहस्य-रोमांचक श्रृंखला 'शक: ट्रस्ट नो वन' की प्रदर्शन तिथि घोषित कर दी गई है। इस श्रृंखला का निर्माण चर्चित फिल्म निर्माता सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने किया है, जबकि इसका निर्देशन रेनसिल डी' सिल्वा ने किया है। पहले इस श्रृंखला का नाम 'तलाश: ए मदर्स सर्च' रखा गया था, जिसे अब बदलकर 'शक: ट्रस्ट नो वन' कर दिया गया है। निर्माताओं के अनुसार, बदला हुआ नाम श्रृंखला की रहस्यमय कहानी और उसमें मौजूद संदेह के माहौल को बेहतर तरीके से दर्शाता है। डिजिटल मंच नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला के प्रदर्शन की तारीख की घोषणा की है। मंच की ओर से श्रृंखला का पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया, शक की सुई चल पड़ी है, तारीख नजदीक आ रही है। 'शक: ट्रस्ट नो वन' को 24 सितंबर, 2026 से नेटफ्लिक्स के सदस्य दर्शक देख सकेंगे। श्रृंखला की घोषणा इसी साल की शुरुआत में की गई थी और तब से परिणीति चोपड़ा के प्रशंसकों के बीच इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई थी। 'शक: ट्रस्ट नो वन' की कहानी एक मां और उसके नौ साल से लापता बच्चे की तलाश के इर्द-गिर्द घूमती है। बच्चे के अचानक गायब होने के बाद मां उसकी तलाश में जुटती है। इस दौरान उसके सामने कई ऐसे सवाल और रहस्य सामने आते हैं, जो कहानी को रहस्य और रोमांच से भर देते हैं। श्रृंखला में परिणीति चोपड़ा के अलावा ताहिर राज हुसैन, सोनी राजदान, जेनिफर विंगेट, व्यास सुमित और हर्लिन सेठी जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस श्रृंखला का निर्माण सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने किया है। वह भविष्य में दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी के जीवन पर आधारित जीवनीपरक फिल्म भी लेकर आने वाले हैं। वहीं 'शक: ट्रस्ट नो वन' का निर्देशन रेनसिल डी' सिल्वा ने किया है, जो रहस्य और गंभीर विषयों को पढ़ें पर प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। परिणीति चोपड़ा की डिजिटल मंच पर वापसी और रहस्य से भरपूर कहानी के कारण 'शक: ट्रस्ट नो वन' को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। अब 24 सितंबर को इसके प्रसारण के बाद यह देखा होगा कि श्रृंखला दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।



धनुष की फिल्म ओम : चैप्टर 1 से ममूटी का दमदार अवतार आया सामने

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी ने अपने फैस को शानदार तोहफा दिया है। उन्होंने सुपरस्टार धनुष की आगामी फिल्म ओम: चैप्टर 1 से अपने किरदार की एक झलक दिखाई है, जिसके जरिए वह तमिल सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। राजकुमार पेरियासामी द्वारा निर्देशित इस फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर जारी हुआ है, जिसमें ममूटी को केंद्र में दिखाया गया है। उनकी उपस्थिति फिल्म में एक्शन, इमोशन और स्टाइल के मिश्रण का संकेत देती है।

ओम: चैप्टर 1 के टीजर में, ममूटी को कार्टिकेय के रूप में दिखाया गया है, जो सिया नाम से जुड़ा एक किरदार है और जिसे एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर के रूप में वर्णित किया गया है।

उनकी दमदार उपस्थिति से पता चलता है कि फिल्म में उनका किरदार शक्ति और भावनात्मक गहराइयों से भरपूर होगा। कहानी को फिलहाल गुप्त रखा गया है।

इसके जरिए ममूटी 7 साल बाद तमिल सिनेमा में लौटे हैं। उनकी आखिरी फिल्म पेरंबु (2019) थी।



धनुष अपनी वंडरबार स्टूडियोज और आरटेक स्टूडियोज की साझेदारी में ओम: चैप्टर 1 का निर्माण कर रहे हैं। इसका संगीत साईं अन्थर्कर ने संगीत दिया है। फिल्म में उनके साथ साईं पल्लवी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। वहीं, श्रीलीला एक

अहम किरदार में शामिल होंगी। नसीरुद्दीन शाह भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं और यह उनकी पहली तमिल फिल्म होने वाली है। यह 16 अक्टूबर, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

रिलीज से पहले 'वाइब' का छाया खुमार, कुणाल खेमू की फिल्म का टाइटल ट्रैक 'ऐसी मेरी वाइब' जारी

अभिनेता कुणाल खेमू की आगामी फिल्म 'वाइब' अपनी रिलीज से पहले ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले बनी इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म के ट्रेलर को कुछ दिन पहले जारी किया गया था, जिसे दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। अब निर्माताओं ने फिल्म का शीर्षक गीत 'ऐसी मेरी वाइब' जारी कर दिया है। गाने में फिल्म के सभी प्रमुख कलाकार एक साथ नृत्य करते नजर आ रहे हैं। इसका फिल्मांकन कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर पर किया गया है। गाने में कुणाल खेमू और स्पर्श श्रीवास्तव का जोशीला नृत्य खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

'ऐसी मेरी वाइब' को खिलारी, इरफाना और कन्प्यूजन ने अपनी आवाज दी है। कनिष्क पाल ने गाने का संगीत तैयार किया है, जबकि इसके बोल शुभम सोपान, खिल्लारी और इरफाना हमीद ने लिखे हैं।

तेज और जोशीले संगीत से भरपूर यह गाना युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। गाने में फिल्म के प्रमुख कलाकारों की



ऊर्जा और नृत्य का अंदाज देखने को मिलता है। माना जा रहा है कि इसकी धुन और प्रस्तुति दर्शकों को थिरकाने के लिए मजबूर कर सकती है।

इससे पहले 'वाइब' का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे दर्शकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर में एक्शन और हास्य का

मिश्रण देखने को मिला था। फिल्म की कहानी और कलाकारों के किरदारों को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है। फिल्म का निर्देशन और कहानी से जुड़ी अन्य जानकारी निर्माताओं की ओर से धीरे-धीरे सामने लाई जा रही है। टाइटल ट्रैक जारी होने के बाद फिल्म के प्रचार अभियान को भी गति मिलने की उम्मीद है।

